terms specified in the Protocol. The formula for sharing the loss as between the farmers and the Agro-Industries Corporations is under active consideration of the latter.

देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए अविलम्बनीय कार्यक्रम

476. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री बी० के० दासचौधरी :
श्री डी० के० पडा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए नियत 50 करोड़ रुपयों का उपयोग करने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त करने को कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त विचारों का ब्योरा क्या है तथा उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख). वर्ष 1971-72 में 50 करोड़ रु० के परिव्यय की ग्राम रोजगार की त्वरित योजना बनाई गई है। यह योजना केन्द्रीय सरकार की शत प्रतिशत वित्तीय सहायता से राज्य सरकारों, केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। अतिरिक्त रोजगार श्रम-प्रधान तथा स्थायी स्वरूप की परिसम्पत्तियां तैयार करने वाली विभिन्न किस्मों की ग्राम परियोजनाओं के जाल के माध्यम से पैदा करने का इरादा है। प्रत्येक जिले मे कम से कम 1,000 व्यक्तियों को वर्ष भर में दस महीनों के लिए 100 रु० प्रतिमास तक मजदूरी पर रोजगार दिया जाना है। मजदूरी की लागत के एक चौथाई के बराबर की राशि सामग्री तथा उपकरणो के लिए उपलब्ध होगी। परिव्यय की राशि 12.50 लाख रु० प्रति जिला प्रति वर्ष होगी।

(ग) और (घ). यह योजना राज्यो को भेजी गई थी। बारह राज्य सरकारे और सात केन्द्र शासित प्रशासन प्रस्ताव भेज चुके है, जिनमें इस योजना के अन्तर्गत आरम्भ की जाने वाली कुछ परियोजनाओ का ब्यौरा दिया गया है। आठ राज्यो और छ केन्द्र शासित क्षेत्रो के प्रस्तावो को कार्यान्वित करने के लिए मजूरी दे दी गई है। शेष राज्यो के प्रस्तावो की जांच की जा रही है।

Import of Suitable Tractors in Replacement of Defective RS-09 Tractors Imported from G.D.R.

478. SHRI R. S. PANDEY : Will the Minister of AGRICULTURE (KRISHI MANTRI) be pleased to state :

(a) whether all the tractors imported from East Germany which were found defective have since been returned to that country ;

(b) the arrangements made by the Government to import better tractors in replacement of defective RS-09 tractors for supply to farmers to whom they were meant to be supplied ;

(c) when the new tractors are likely to be procured and supplied to the farmers ; and

(d) the steps taken to ensure that the new tractors are found suitable to the requirements of the Indian farmers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE) : (a) A Protocol about the return of modified RS-09 tractors was signed between the State

Trading Corporation and the GDR Suppliers on the 21st February, 1271 A copy of the Protocol is laid on the Table of the House [*Placed in Library See* No LT-212/71] The concerned State Agro Industries Corporations are taking steps to arrange return of modified RS-09 tractors according to the terms of that Protocol

(b) to (d). No special arrangements have been made to import tractors in replacement of defective RS-09 tractors However, the concerned State Agro-Industries Corporations have been advised to arrange replacement of RS-09 tractors with popular makes of tractors such as Zetor, and Ursus to the extent possible In case where the farmers do not wish for any other tractor, the Corporations could consider the question of repayment in cash in consultation with the financial institution that had advanced the loan in the first instance Allotment of these tractors has already been made by this Ministry to the concerned State Agro-Industries Corporations out of current import More tractors will be allotted to them according to their availability

आयातित खाद्यान्नो पर भाडा

479. **श्री हुकम चन्द कछवाय** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1969-70 और 1970-71 मे विदेशो स आयातित खाद्यान्नो को इधर उधर ले जाने पर भाडे के रूप म कितना खर्च किया गया, और

(ख) वित्तीय वप 1971 72 म इस उद्देश्य के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क)

वर्ष	समुद्री भाडे की अनुमानित राशि करोड़ रुपयो में
1960-70	51 09
1970-71	48,55

(यह खर्चा भारतीय खाद्य निगम जिनके खाते मे आयात किया गया था द्वारा किया गया था।)

(ख) 1971-72 मे समुद्री भाडे पर 35 करोड रुपये के आस-पास खर्च हो सकता है।

Decline in Coal Production

480 SHRI INDRAJIT GUPTA . Will the Minister of STEEL AND MINES (ISPAT AUR KHAN MANTRI) be pleased to state

(a) whether Government propose to reduce and cut down the target of coal production fixed in Fourth Plan in view of the serious decline in coal production in 1970 ,

(b) if so, the specific reasons of this decline

(c) whether Government propose to build major thermal plants and undertake other measures in order to prevent further decline in coal production and reach the anticipated target , and

(d) if not the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) (a) No, Sir The target of coal production will, however, be reviewed periodically having regard to the trend of consumption and the progress in the programmes of the consuming industries

(b) The decline in the production was mainly due to shortage of wagons for the transport of coal and the reduced off-take of coal by steel plants etc

(c) and (d) Setting up of many major thermal power stations is already envisaged in the Fourth Five Year Plan and more may be taken up in the subsequent Plans. There are similar developmental programmes in some of the other major coal consuming sectors. The Government have set up a High Powered Committee to recommend a